

प्रदेश को माइक्रोप्रोसेसर मैनुफेक्चरिंग का हब बनाने की तैयारी में आईआईटी

अनुमति और फंड जुटाने के लिए संस्थान एमएचआरडी को भेजेगा प्रस्ताव

गजेंद्र विश्वकर्मा | इंदौर

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) इंदौर प्रदेश को माइक्रोप्रोसेसर (कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली चिप) मैनुफेक्चरिंग हब बनाने पर काम कर रहा है। इसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन और मैनुफेक्चरिंग करने वाले संस्थानों के विशेषज्ञों को शहर में आमंत्रित कर इसकी संभावनाओं पर बात हो रही है। इस समय देश में चंडीगढ़ और बैंगलुरु में माइक्रोप्रोसेसर मैनुफेक्चरिंग हो रहा है। विशेषज्ञों ने आईआईटी इंदौर को प्रदेश में मैनुफेक्चरिंग का सेटअप तैयार करने के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। आईआईटी इसकी अनुमति और फंड जुटाने के लिए एमएचआरडी को प्रस्ताव भेजेगा।

आईआईटी द्वारा जुलाई के पहले सप्ताह में शहर में वेरी लॉर्ज स्केल इंटीग्रेशन (वीएलएसआई) डिजाइन के लिए इंटरनेशनल कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। इसमें दुनियाभर के माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन और मैनुफेक्चरिंग करने वाली



कंपनियों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। इसमें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आने वाले सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) के भी अधिकारी आए थे। उन्होंने भी आईआईटी को प्रदेश में जमीन तलाशने की बात कही। आईआईटी इंदौर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संतोष कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि संस्थान के पास माइक्रोप्रोसेसर बनाने के सभी संसाधन मौजूद हैं। प्रदेश में इसके लिए अच्छा वातावरण भी है। देश का तीसरा माइक्रोप्रोसेसर यूनिट प्रदेश में स्थापित करने के लिए काम रहे हैं। इंटरनेशनल कांफ्रेंस में हमारा मकसद प्रदेश में इसकी संभावनाओं पर भी बात करना था। इसके लिए देश में काम कर रहे

एसजीएसआईटीएस भी कर रहा प्रयास

माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन और मैनुफेक्चरिंग यूनिट शुरू करने की कोशिश में शहर का एसजीएसआईटीएस संस्थान भी कोशिश कर रहा है। इसरो के कुछ अधिकारियों से इस संबंध में संस्थान ने बात भी कही है। संस्थान के डायरेक्टर डॉ. आरके सक्सेना का कहना है कि प्रदेश में आईआईटी और एसजीएसआईटीएस ऐसे संस्थान हैं, जहां माइक्रोप्रोसेसर से संबंधित सभी आधुनिक साधन मौजूद हैं। आईआईटी अगर हमारे साथ मिलकर यूनिट स्थापित करना चाहता है तो भी हम इसके लिए तैयार हैं।

उन संस्थानों की मदद चाहिए, जहां पहले से इसे डिजाइन और मैनुफेक्चरिंग किया जा रहा है। इसमें से एससीएल ऐसे शिक्षण संस्थानों को बिना शुल्क माइक्रोप्रोसेसर बनाकर देता है। इनके अधिकारियों ने हरसंभव मदद की बात कही है। अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।